pect of Anola project referred to irregularities involving over payments to the contractors. The complaints regarding gunny bags related to purchases made through Central Purchase Committee that had been constituted to recommend purchases for public and cooperative sector fertilizer companies. In regard to these purchases there were allegations of undue favours shown to private firms. No complaints have however been received from any of the foreign countries or the World Bank.

Enquiries are being conducted by IFFCO in respect of the irregularities in the payments involved in the execution of the Anola Project. The matter has also been referred to the Central Bureau of Investigation. The matter concerning purchase of gunny bags made through the Central Purchase Committee has also been referred to CBI. CBI has already registered a regular case against the members of the Central Purchase Committee and also a private party.

(d) In addition to the normal audit by the Statutory Auditors, the Comptroller and Auditor General of India has been requested to conduct audit of IFFCO. The Anola expansion plan has not yet been cleared by the Government.

मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा

866. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने 11 और 12 जुलाई, 1990 को दिल्ली में पंचायती राज प्रथा के सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त भूमि के वितरण तथा शहरी एवं ग्रामीण भूमि/संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करने के लिये राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया ; यदि हां, तो उस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन 11 व 12 जून, 1990 को नई दिल्ली में कुछ विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिये आयोजित किया गया था जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना और शहरी तथा ग्रामीण भूमि/संपत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना शामिल थे । सम्मेलन में हुई आम राय के आलोक में, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु कानून बनाने तथा भूमि सुधारों के बेहतर कार्यान्वियन हेतु मार्गदर्शिकायें तैयार करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

महिला होस्टलों से निवासियों का निकाला जाना

867. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1990 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "इनमेट्स आफ वीमेन्स होस्टल डैली बीइंग इविक्टिड" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन होस्टलों में रह रही महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) जो लोग इन होस्टलों का वाणिज्यिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या इन होस्टलों से निष्कासित महिलाओं को कहीं और आवासीय सुविधायें दी गई हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार, आल इंडिया वीमेन्ज कानफ्रेंस और दिल्ली महिला समाज द्वारा दिल्ली में चलाये जा रहे दो कामकाजी महिला होस्टलों में कथित अनियमितताओं के संबंध में है। इन दोनों मामलों में विस्तृत जांच की गई थी।

(ग) 400 निवासियों की क्षमता वाले इन होस्टलों में 292 निवासी हैं।

(घ) सरकार ने आल इंडिया वीमेन्ज कानफ्रेंस को अनुदेश दिये हैं कि केन्द्रीय सरकार की सहायत से बने होस्टल का कोई भी हिस्सा, योजना के अनुसार, पात्र कामकाजी महिलाओं को होस्टल आवास उपलब्ध कराने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जहां तक दिल्ली महिला समाज द्वारा चलाये जा रहे होस्टल का संबंध है, इस संगठन को दी गई सरकारी अनुदान राशि वापिस लेने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) इस योजना का उद्देश्य ऐसी प्रवासी कामकाजी महिलाओं को, जिनकी आय (समेकित) 3000/- रू. प्रति मास से अधिक न हो, तीन वर्ष तक के लिये आवास उपलब्ध कराना है। यह अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अतः योजना में स्थायी आधार पर आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है।

Relief to Vanaspati industry

1968. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the percentage of production of vanaspati in the total edible oil supply in the country in 1989-90;

(b) what is the rationale of offering various concessions such as excise duty relief to the vanaspati industry when the producers of other edible oils are not extended any such fiscal or other incentives; and

(c) whether it is a fact that vanaspati is mostly used by commercial establishments such as hotels and sweetmeat shops and not by house-holds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) The production of vanaspati is about 20 per cent of the total edible oils supply in the country during the year 1989-90.

(b) The rationale of offering excise duty relief to vanaspati industry is to give encouragement to the production of minor/non-conventional oils as also to provide benefit to the consumers. The manufacturers of non-conventional oils also get the benefit by way of better price of their produce.

(c) No, Sir. According to the study conducted by National Council of Applied Economic Research, the house-hold consumption of vanaspati formed nearly 61 per cent of the despatches in the year 1982-83.

जवाहर रोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश में कुओं की खुदाई

1969. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के तहत 10 लाख कुएं खोदे जाने के निर्धारित लक्ष्य के अधीन वर्ष 1989 के अन्त तक मध्य प्रदेश में कितने सफल कुओं का निर्माण किया गया तथा उस पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इन सफल और असफल कुओं का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

कृषि संत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :

(क) दस लाख कुओं की योजना को पहले के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम